भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4927
उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

नए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना

4927. **श्री देवेश शाक्य:**
श्री बाबू सिंह कुशवाहा:
श्री नीरज मौर्य:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज, जौनपुर, बदायूं और बरेली जिलों और आंवला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों के युवाओं के लाभ के लिए नए केंद्रीय शिक्षण संस्थान या व्यावसायिक/कौशल आधारित महाविद्यालय स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान एटा, कासगंज, जौनपुर, बदायूं और बरेली जिलों के सरकारी महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं और डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए स्वीकृत की गई और उपयोग की गई निधि कितनी है;
(ग) क्या सरकार का जौनपुर, एटा, कासगंज और आंवला क्षेत्र के स्थानीय महाविद्यालयों में कृषि-उद्यमिता का संवर्धन करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता या विशेष अनुदान प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने विशेषकर एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों में ग्रामीण छात्रों को शैक्षिक ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु कोई विशेष निगरानी तंत्र या सहायता प्रणाली स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), अलीगढ़, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी (बीएचयू), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) प्रयागराज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) इलाहाबाद आदि सहित 15 केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थान हैं।

सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसा के पूर्ववर्ती चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियों सहित 12,926.10 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का तीसरा चरण शुरू किया है। पीएम-उषा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

उत्तर प्रदेश राज्य में, योजना के विभिन्न घटकों के तहत, 1942.27 करोड़ रु. (इसमें से 1173.06 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा) की राशि के लिए कुल 204 इकाइयों को स्वीकृति दी गई है जिसमें एटा, कासगंज, जौनपुर, बदायूं और बरेली जिलों में न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज, बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु), विश्वविद्यालयों के सुदृढीकरण करने के लिए अनुदान (जीएसयू) और कालेजों के सुदृढीकरण करने के लिए अनुदान (जीएसयू) के लिए 217.64 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाए शामिल हैं। इसके अलावा, योजना के विभिन्न घटकों के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कई कार्यकलाप जैसे (i) उद्योगों/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की मदद से कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के लिए स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन केंद्र और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र स्थापित करना; (ii) प्रशिक्षुता/अनुसंधान/उद्यमिता/रोजगार के लिए उद्योग के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए; (iii) नियुक्ति/प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम, उद्योग के लिए अधिक उपयुक्त संवर्धित पाठ्यक्रमों और उद्योग-अकादमिक संबंधों के अनुरूप संरचनात्मक सुधार; (iv) इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता एंबेडेड डिग्री कार्यक्रम; (v) 21वीं सदी के कौशलों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में इंटर्नशिप/प्रशिक्षण; (vi) महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए कौशल और व्यवसायीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/प्लेसमेंट पर ध्यान केंद्रित करना; (vii) नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के माध्यम से छात्रों के लिए समानता और गतिशीलता स्थापित करना; (viii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता कार्यढांचा; (ix) एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), बहु प्रवेश/निकास; (x) भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम और पुस्तकें/पाठ्यक्रम सामग्री आदि शुरू कर सकते हैं।

(घ): शैक्षिक ऋण प्राप्त करते समय ग्रामीण छात्रों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in विकसित किया गया है, जिस पर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों सहित छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली आसान आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज से छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल ने 25 फरवरी 2025 से काम करना शुरू कर दिया है। पूर्व में उपयोग किए जाने वाले 7-8 पृष्ठ के लंबे प्रारूप की अपेक्षा 2-पृष्ठ के एक सरल आवेदन प्रारूप के साथ ऋणों को सरलीकृत, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ बनाया जाता है। आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में छात्रों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और बैंकों की मदद के लिए पीएमवीएल पोर्टल आवेदनों के लिए 24X7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 1031 चालू है। वर्ष 2025-26 (फरवरी 2026 तक) में पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के छात्रों को 25,000 से अधिक शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

*****